

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3174/111/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 18.03.

2015 पारित द्वारा - आयुक्त, सागर संभाग, सागर-प्रकरण क्रमांक 84

अ-19/2004-05 निगरानी

शंकर सिंह पुत्र धनु ढीमर
ग्राम मैदवारा तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
विरुद्ध

— आवेदक

1- रामसिंह पुत्र फेरन सिंह
ग्राम मैदवारा तहसील पलेरा
जिला टीकमगढ़ म०प्र०

2- म.प्र.शासन

— अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

(अनावेदक क्र-1 अनुपस्थित)

(अनावेदक क्र-2 की ओर से पेनल लायर)

आ दे श

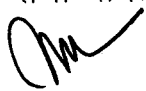
(आज दिनांक 31-8-2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 84 अ-19/
2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-3-2008 के विरुद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता
1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।



2 प्रकरण का सारंश यह है कि नायव तहसीलदार लिधोरा जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 72 अ 19/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 20.11.1985 से ग्राम मेंदवारा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2197 रकबा 1.484 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत अनावेदक क्रमांक-1 के नाम व्यवस्थापित की। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, जतारा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 75/88-89 एवं 48 बी 121/1989-90 में दिनांक 16-5-90 को इस आशय का आदेश पारित किया कि म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत अपील के श्रवणाधिकार न होने से प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को भिजवाया जाय। अनुविभागीय अधिकारी जतारा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 216/1989-90 पंजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 04-08-1990 पारित किया एवं अनावेदक क्रमांक-1 को पट्टा प्राप्ति हेतु अपात्र होते हुये भी भूमि व्यवस्थापन किया जाना पाये जाने के कारण नायव तहसीलदार लिधोरा जिला टीकमगढ़ का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 20.11.1985 निरस्त कर दिया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि यदि आवेदक व्यवस्थापन हेतु पात्र पाया जाय, तो पात्रता की जांच कर उसे पट्टा प्रदान किया जावे।

अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 20.11.1985 के विरुद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 20.11.85 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ, जिस पर से कलेक्टर टीकमगढ़ ने निगरानी प्रकरण क्रमांक 65 /1997-98 दर्ज किया तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई हेतु आहुत किया। कलेक्टर टीकमगढ़ ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16.12.2003 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक क्रमांक-1 को भूमिस्वामी दर्ज किये



जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर प्र0कमांक 84 अ 19/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 18.3.2008 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक एवं अनावेदक क-2 के अभिभाषकों के तर्क सुने। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

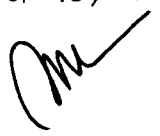
4/ उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि रामसिंह पुत्र फेरन सिंह अनावेदक क-1 द्वारा आवेदन करने पर नायब तहसीलदार लिधोरा ने प्रकरण कमांक 72 अ 19/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 20.11.1985 से वादग्रस्त भूमि म0 प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विषेय उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत व्यस्थापित की है और यह भी सत्य है कि इस आदेश को अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 216 स्वमेव निगरानी/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 04 अगस्त 1990 से निरस्त करते हुये भूमि पुनः शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष निगरानी होने पर अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 4-8-90 को निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित हुआ है कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद पुनः निर्णय लिया जावे और पुनः सुनवाई के निर्देश अपर कलेक्टर टीकमगढ़ को दिये गये हैं। इसके बाद कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में निगरानी कमांक 65 /1997-98 दर्ज की जाकर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16.12.2003 से वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक कमांक-1 को भूमिस्वामी दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं और इस आदेश को आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण कमांक 84 अ 19/04-05 में पारित आदेश दिनांक 18.3.2008 से स्थिर रखा है। प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि जब नायब तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दिनांक 20.11.85 को अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 4-8-90 से निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दे दिये थे, तब प्रकरण में ऐसी कौनसी परिस्थितियाँ उपजीं कि वादग्रस्त भूमि पुनः

अनावेदक क्र-2 के नाम दर्ज करना लाजमी हुआ ? कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 16-12-03 के पद 2 में निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक क्र-2 द्वारा वर्ष 1984 के कब्जे की खसरा की प्रति एवं 2 अक्टूबर 1984 के कब्जे की सूची प्रस्तुत की जिसमें अन्य कृषकों के साथ अनावेदक का भी प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा पाया गया है, जबकि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 216/89-90 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 अगस्त 1990 में निष्कर्ष दिया है कि :-

“ ग्राम मेंदवारा की ही कुछ अन्य भूमियों जिनके कब्जे को लेकर ग्रामवासियों तथा पट्टाग्रहीताओं के मध्य गंभीर झगड़ा हुआ और दिनांक 25.6.90 को 4 व्यक्तियों का कत्ल हुआ है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा प्रदान किये गये पट्टे की विश्वसनीयता की जांच के लिये कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा तहसीलदार जतारा को आदेश क्रमांक 831/स्टोनो/90 में दिनांक 27-6-1990 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार जतारा द्वारा दिनांक 7-7-90 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने स्थल की जांच करने के बाद यह पाया कि गैरनिगरानीकार रामसिंह तनय फेरन सिंह निवासी मेंदवारा का विवादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार जतारा द्वारा यह भी निष्कर्ष निकाला कि रनमत सिंह, रामसिंह तनय फेरन सिंह के नाम ग्राम पचघरा में 4-90 एकड़ भूमि है इसलिये उक्त अधिनियम के अंतर्गत पट्टा प्राप्त करने के लिये पात्रता नहीं रखते हैं।”

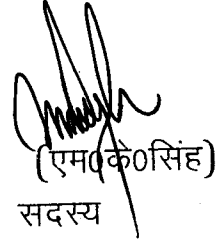
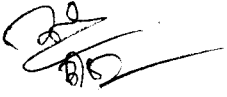
उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनावेदक को भूमि व्यवस्थापित कराने की कतई पात्रता नहीं है क्योंकि उसके एवं उसके भाई रनमतसिंह के नाम ग्राम पचघरा में पूर्व से ही 4-90 हैक्टर भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि पर अनावेदक क्र-1 का कभी भी मौके पर कब्जा नहीं रहा है इसके बाद भी कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 65 /1997-98 आदेश दिनांक 16.12.2003 से आवेदक 2-10-84 से कब्जा मानना एवं अनावेदक क्र-1 के अपात्र होते हुये भी वादग्रस्त भूमि का त्रुटिपूर्ण ढंग से व्यवस्थापन करना पाया गया है जिसके कारण उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-12-2003 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 84 अ-19/ 2004-05 निगरानी में आदेश दिनांक 18-3-2008 पारित

28/8/08



करते समय उपरोक्त वर्णित तथ्यों को जानबूझकर नजरन्दाज करते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 16-12-03 को स्थिर रखने की त्रुटि की गई है जिसके कारण आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 84 अ-19/ 2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-3-2008 तथा कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 65 / 1997-98 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2003 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 65 / 1997-98 में पारित आदेश दिनांक 16.12.2003 एवं आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 84 अ-19/ 2004-05 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18-3-2008 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। परिणामतः अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 216/89-90 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 04 अगस्त 1990 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।



(एम0के0सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर